under rehabilitation package prepared by financial institution is provided by State Govt, to the maximum limit of Rs 5.00 lakhs).

(iv) The State Level Inter-institutional Committee wherein representatives from RBI, SIDBI and commercial banks are also members takes up various matters relating to rehabilitation of SSI units.

(v) The Uttar Pradesh Financial Corpn., a lead financial institution for SSI sector is giving various concessions for rehabilitation of such units. These concessions are in the shape of additional loan, reschedulement oi old dues, one time settlement, etc. in coordination with the commercial banks.

(vi) Through the mechanism *oi* UDYOG BANDHU—a focum for redressal of grievances of industrial units at district, divisional and at state level, cases of sick units under rehabilitation are actively pursued with the concerned agencies.

(vii) At the instance of the Centra] Government, the RN had constituted a committee under the Chairmanship of Ex-Dy. Governor, Shri P.R. Nayak, which submitted its report in Sept, 1992. The Committee looked into the problems of credit, sickness and other relevant aspects. The committee has made several recommendation for thg revival of sick units which include a modified definition of sick SSI units, creation of separate cells by banks, setting up of State Level Tribunals, use of DICs as a forum for redressal of grievances, revitaHsation of State Level Tnter-Insritutional Committee, etc. The RBI has already announed its decision on some of its recommendations such as modified definition of sick units and reduced rate of interest to be charged on the rehabilitation of sick units.

देश में निर्मित साइकिलें

965. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष कितनी साईकिलों का निर्माण किया गया,

(ख) देश में इस समय साइकिल निर्माण के कितने एकक हैं और वे कहां-कहां पर स्थित है, और

(ग) इन एककों को उक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुए निर्यात-आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान साइनिलों का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	संख्या लाख में
1990-91 . . .	70.84
1991-92 . . .	71.50
1992-93 . . .	69.64

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) देश से पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी साइकिलों और हिस्सों का निर्यात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	रु० करोड़ में (अन्तिम)
1990-91 . . .	140.00
1991-92 . . .	300.00
1992-93 . . .	445.00

विवरण

क्र०सं०	नाम	स्थापना स्थल
1	मैसर्स हीरो साइकिल (पी) लि०	लुधियाना
2	मैसर्स एटलस साइकिल इण्ड० लि०	सोनीपत
3	मैसर्स हीरो साइकिल लि०	मेरठ
4	मैसर्स टी०आई० साइकिल ऑफ इंडिया	मद्रास
5	मैसर्स नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन लि०	मेरठ
6	मैसर्स साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया	बरद्वान
7	मैसर्स रोडमास्टर इण्ड० ऑफ इंडिया	पटियाला
8	मैसर्स एटलस साइकिल लि०	मेरठ
9	मैसर्स नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन लि०	बम्बई
10	मैसर्स एवन साइकिल लि०	लुधियाना
11	मैसर्स गुजरात साइकिल लि०	बड़ौदरा

उपर्युक्त 11 एकक संगठित क्षेत्र में हैं।

मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक एककों की स्थापना

965. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 30 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े आवेदन-पत्र/प्रस्तावों की जिला वार संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रस्तावों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इन औद्योगिक एककों मे रोजगार के कितने अवसरों का सृजन होने की सम्भावना है;

(घ) इन संयुक्त उद्यमों से कुल कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है;

(ङ) प्रत्येक एकक में कितनी पूंजी का निवेश किये जाने की सम्भावना है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(च) क्या सरकार ने सभी उद्यमियों के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए 30.11.93 को लम्बित पड़े औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न (नीचे देखिए) है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त आवेदनों में प्रस्तावित अचल संपत्ति में विदेश और प्रस्तावित रोजगार क्रमश: 1223.17 करोड़ रुपये तथा 15265 व्यक्ति है।

(घ) और (ङ) संयुक्त उपक्रम हेतु विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में परियोजना के स्थापना स्थल का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए, विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाले संयुक्त उपक्रमों के प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जा रहा है।

(च) औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए सभी आवेदनों पर औद्योगिक नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।